शनिवार

08 अगस्त 2026

- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 196
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

# दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

# भाजपा का स्लोगन 'पैसा बोलता है' : खड़गे

संवाददाता

हल्द्वानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि भाजपा का स्लोगन है कि पैसा बोलता है।

आज यहां हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि कांग्रेस ने जो बोला वह करके दिखाया है। लेकिन भाजपा नौकरियां बेच रही है उनका स्लोगन है कि पैसा बोलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि वीरों की भूमि है यहां पर लोग शांति के साथ काम करते हैं। उन्होंने वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार आयेगी तो बिना रिश्वत व सिफारिश के नौकरियां दी जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग होशियार है आज देश में सबसे अधिक नौकरशाह उत्तराखण्ड के हैं।

खड़गे ने जंतर मंतर में छात्रों के आंदोलन पर कहा कि पेपर लीक का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे छात्रों पर मोदी सरकार ने लाठियां चलवायी, आंसू गैस के गोले छोड़े, बेलेट गन चलवायी, छात्राओं को घसीटा गया और उनको सारी रात थाने में बैठाये रखा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया यह कांग्रेस की नीति है। जबकि भाजपा की नीति पीटने की है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों, मजदूरों का हक छीनने का कार्य किया वहीं कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 72 हजार करोड का किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा कि सरकार में 30 लाख वैकेंसी है लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ विकसित भारत का नारा देते हैं। उन्होंने कहा कि वह सीढियां चढकर ऊपर आये है लेकिन भाजपा जिसको जेल भेजती है उसको ही अपनी वाशिंग मशीन में धोकर भाजपा का सदस्य बना देती है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्या कुमारी से कश्मीर तक पैदल चले वह भी संविधान बचाने के लिए चले। उन्होंने कहा कि भाजपा के नरेन्द्र मोदी, अमित शाह या कोई ऐसा नेता है जोकि गरीब किसानों, विद्यार्थियों से मिलने के लिए चला हो, कोई नहीं है। जबकि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से वायदा किया था कि हर साल दो करोड नौकरी दूंगा। कोई इनसे पूछे कि 15 साल से गद्दी पर बैठे हैं जिसके चलते अभी तक 25 करोड नौकरी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है इनका काम झूठ बोलना है। यह जनता को अपने झूठे वायदों में फंसाकर गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांण्ड का भी जिक्र किया कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने में देर इस लिए हुई क्योंकि उसमें भी भाजपा के नेता शामिल थे। इस मौके पर मंच पर उनके साथ उत्तराखण्ड कांग्रेस के नेता मौजूद रहे।

## एसआईआर में 75 साल के बुजुर्ग से दस्तावेज मांगने पर उठ रहे हजारों सवाल

# 75 साल की उम्र, 50 साल का वोट व एक हाईस्कूल मार्कशीट की जलालत

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। एक आदमी 75 साल का हो चुका है। उसके बाल सफेद हैं। चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं। जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसने इसी देश में गुजारा है। उसने सरकारें बदलते देखीं। प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा। मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले। चुनाव के नारों को बदलते देखा। गांवों को कस्बों में बदलते देखा और कस्बों को शहर बनते देखा और इन तमाम बदलावों के बीच एक चीज नहीं बदली उसका वोट। करीब पांच दशक तक वह चुनाव आया तो मतदान केंद्र तक गया। कतार में खड़ा हुआ। पहचान बताई। वोट डाला और घर लौट आया। लेकिन आज, 75 साल की उम्र में व्यवस्था उसके सामने एक नया सवाल लेकर खड़ी है हाईस्कूल की मार्कशीट दिखाइए। यह सिर्फ एक कागज मांगने की कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते की कहानी है जो नागरिक और लोकतंत्र के बीच बनता है और सवाल यह है कि क्या पांच दशक तक वोट देने वाला नागरिक आज एक मार्कशीट से छोटा हो गया है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। फर्जी नाम हटें, मृत मतदाताओं के नाम हटें, गलत प्रविष्टियां सुधरें और वास्तविक मतदाता सूची में रहें इस उद्देश्य पर सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल उस तरीके पर है, जिसमें प्रक्रिया आम आदमी के लिए भय और परेशानी का कारण बनने लगे। एक 75 वर्षीय व्यक्ति से हाईस्कूल की मार्कशीट मांगना शायद कागज पर एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगे। लेकिन उस व्यक्ति की जिंदगी में जाकर देखिए। उसने हाईस्कूल किस साल पास किया होगा। उस समय स्कूलों में रिकार्ड आज की तरह डिजिटल नहीं थे। कितने स्कूलों की पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। कितने स्कूलों के पुराने रजिस्टर सुरक्षित हैं। कितने लोगों के पास 50-60 साल पुराने प्रमाणपत्र आज भी सुरक्षित होंगे और अगर वह कागज खो गया तो क्या नागरिकता, मतदाता पहचान और लोकतांत्रिक अधिकार का पूरा भार अब एक पुराने कागज पर टिका दिया जाएगा।

व्यवस्था कह सकती है दस्तावेज तो चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर अगला सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है। 75 साल का बुजुर्ग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए, स्कूल की पुरानी फाइल खोजे, तहसील जाए, ब्लाक जाए, जन्म प्रमाणपत्र तलाशे, पुराने रिकार्ड निकलवाए और अगर रिकार्ड किसी दफ्तर में उपलब्ध ही नहीं है तो फिर क्या। क्या उसे यह साबित करना होगा कि वह पिछले 50 वर्षों से वोट क्यों देता आया। क्या वह अपनी जिंदगी की गवाही लेकर सरकारी दफ्तर में खड़ा होगा। यह वही देश है जहां गांव का एक बुजुर्ग पूरे इलाके को पहचानता है और पूरा गांव उसे पहचानता है। लेकिन कागज की दुनिया कहती है गांव तुम्हें जानता हो तो जानता रहे, पहले दस्तावेज दिखाओ। यहीं से लोकतंत्र और कागजी व्यवस्था के बीच की खाई दिखाई देती है।

लोकतंत्र में नागरिक राज्य का मालिक माना जाता है। वह वोट देता है, वह टैक्स देता है, वह कानून मानता है, वह सरकार चुनता है। लेकिन धीरे-धीरे एक ऐसी प्रशासनिक भाषा विकसित होती जा रही है, जिसमें नागरिक से पहले पूछा जाता है आप साबित कीजिए कि आप वही हैं जो आप कहते हैं। यह सवाल सुनने में सामान्य है, लेकिन इसके पीछे छिपा डर बहुत बड़ा है। क्योंकि गरीब के पास दस्तावेज कम हो सकते हैं। बुजुर्ग के कागज खो सकते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति के रिकार्ड पुराने हो सकते हैं। महिलाओं के नाम विवाह के बाद बदल सकते हैं। परिवारों के पते बदल सकते हैं। गांवों के नाम बदल सकते हैं और कई लोगों के जीवन में दस्तावेज हमेशा उनकी जिंदगी से पीछे चलते रहे हैं। तो क्या अब दस्तावेजों की कमी को नागरिक की कमी मान लिया जाएगा।

मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की पहली शर्तों में से एक है। लेकिन मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया में अगर वास्तविक मतदाता ही डरने लगे तो प्रशासन को एक बार रुककर सोचना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग के सामने सिर्फ कागज नहीं हैं। कागज के पीछे इंसान हैं। एक बुजुर्ग है। एक विधवा है। एक प्रवासी मजदूर है। एक पहाड़ी गांव का परिवार है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना अधिकांश जीवन गांव में बिताया और अब उसके बच्चे शहरों में रहते हैं। इन लोगों से दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। लेकिन उन्हें दस्तावेज जुटाने की सहायता दिए बिना सिर्फ नोटिस थमा देना सवाल जरूर खड़ा करता है।

दून वैली मेल

## संपादकीय

# पेपर लीक के विभीषण

नीट यूजी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। यह लाखों परिवारों के सपनों की वह सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर एक बच्चा डाक्टर बनने का सपना देखता है। लेकिन जब इसी परीक्षा की गोपनीयता के भीतर से कोई विभीषण व्यवस्था को धोखा देता है, तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहता सवाल भरोसे के लीक होने का हो जाता है। हर साल लाखों बच्चे नीट यूजी की तैयारी करते हैं। कोई छोटे शहर से आता है, कोई गांव से, कोई साधारण परिवार से। किसी के पास महंगे कोचिंग संस्थान हैं तो कोई किताबों और आनलाइन सामग्री के सहारे तैयारी करता है। महीनों नहीं, कई बार वर्षों तक एक बच्चा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य एक परीक्षा के सामने रख देता है। फिर परीक्षा का दिन आता है। बच्चा परीक्षा केंद्र पहुंचता है। जेब में एडमिट कार्ड होता है और आंखों में डाक्टर बनने का सपना। लेकिन अगर उसी समय किसी दूसरे कमरे में बैठा कोई व्यक्ति पहले से प्रश्नपत्र और उसके जवाबों तक पहुंच बना चुका हो, तो उस बच्चे की मेहनत का क्या अर्थ रह जाता है? यहीं से नीट यूजी पेपर लीक की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रहती। यह मेहनत बनाम पहुंच, ईमानदारी बनाम जुगाड़ और प्रतिभा बनाम व्यवस्था के भीतर बैठे बिचौलियों की कहानी बन जाती है। रामायण में विभीषण लंका के भीतर का व्यक्ति था। आज के संदर्भ में विभीषण शब्द किसी समुदाय या व्यक्ति के लिए आरोप की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उस भीतरी तंत्र का रूपक है, जहां से गोपनीय जानकारी बाहर निकलती है। प्रश्नपत्र आसमान से नहीं गिरता। उसकी छपाई होती है। उसकी पैकिंग होती है। उसकी ढुलाई होती है। उसकी सुरक्षा होती है। परीक्षा केंद्र तक वह पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में जितने हाथ और संस्थान जुड़े हैं, वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसलिए हर बार जब पेपर लीक होता है तो केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि प्रश्नपत्र किसने बेचा। सवाल यह भी होना चाहिए कि वह प्रश्नपत्र उस व्यक्ति तक पहुंचा कैसे? कौन-सी सुरक्षा परत टूटी? किसने नियमों को नजरअंदाज किया? किसने सूचना छिपाई? किसने पैसे लिए? और सबसे महत्वपूर्ण क्या व्यवस्था ने पहले से मौजूद कमजोरियों को जानने के बावजूद उन्हें दूर नहीं किया? पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का होता है, जिसने शायद एक साल अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को दिया था। लेकिन नुकसान यहीं खत्म नहीं होता। उसके माता-पिता का भरोसा टूटता है। कोचिंग व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। परीक्षा संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और अंतत: समाज के मन में यह धारणा मजबूत होती है कि सफलता मेहनत से नहीं, सिस्टम तक पहुंच से मिलती है। यह धारणा किसी भी देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि डाक्टर बनने वाला छात्र सिर्फ परीक्षा पास नहीं कर रहा होता। वह भविष्य में किसी मरीज की जिंदगी संभालने जा रहा होता है। अगर मेडिकल शिक्षा में प्रवेश की पहली सीढ़ी ही भ्रष्टाचार से दूषित हो जाए तो सवाल केवल परीक्षा का नहीं, भविष्य की चिकित्सा व्यवस्था के भरोसे का भी है। पेपर लीक के बाद अक्सर जांच होती है। एफआईआर होती है। गिरफ्तारियां होती हैं। चार्जशीट होती है। राजनीतिक बयान आते हैं। लेकिन जनता को इससे आगे का जवाब चाहिए और उसे हमेशा के लिए बंद कैसे किया जाएगा? किसी एक आरोपी को पकड़ लेना समाधान नहीं है। अगर एक नेटवर्क में दस लोग हैं और उनमें से एक पकड़ा गया, तो बाकी नौ की भूमिका का क्या? अगर किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता किस आधार पर मांगी जा रही है? यह सवाल किसी एक सरकार, पार्टी या संस्था के खिलाफ नहीं है। यह उस व्यवस्था के पक्ष में है जिसमें ईमानदारी से परीक्षा देने वाला बच्चा मूर्ख साबित न हो। नीट जैसी परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही गंभीर होनी चाहिए जैसी किसी अत्यंत संवेदनशील राष्ट्रीय प्रक्रिया की होती है। पेपर की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर स्तर पर डिजिटल और भौतिक निगरानी, सीमित पहुंच, स्पष्ट जवाबदेही और स्वतंत्र आडिट जरूरी हैं। जिस स्तर पर लापरवाही हुई हो, उस स्तर के अधिकारी या संस्था की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सबसे जरूरी जांच की प्रक्रिया पारदर्शी हो। क्योंकि जब परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होगी तो जांच में पारदर्शिता की उम्मीद भी कमजोर पड़ जाएगी। भारत में प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती। यह सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है। एक गरीब परिवार का बच्चा डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या शिक्षक बनकर अपने परिवार की दिशा बदल सकता है। उस बच्चे के पास शायद पैसा नहीं होता, राजनीतिक पहचान नहीं होती, प्रभावशाली रिश्ते नहीं होते। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है मेहनत और अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं उसे यह संदेश दें कि मेहनत से पहले किसी नेटवर्क की जरूरत है, तो हम सिर्फ एक परीक्षा नहीं खराब कर रहे। हम एक पीढ़ी के विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। हर पेपर लीक के बाद किसी एक 'विभीषण' को ढूंढ लेना आसान है। मुश्किल काम है उस पूरी व्यवस्था को बदलना, जिसमें किसी एक व्यक्ति को भीतर से दरवाजा खोलने का मौका मिलता है। इसलिए नीट यूजी पेपर लीक का समाधान सिर्फ आरोपी पकड़ना नहीं है। समाधान है ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें पेपर लीक करना लगभग असंभव हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें परीक्षा से पहले किसी को प्रश्नपत्र की जानकारी मिले तो तुरंत अलर्ट हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें लापरवाही करने वाला अधिकारी भी उतना ही जवाबदेह हो जितना पेपर बेचने वाला और ऐसी व्यवस्था जिसमें लाखों विद्यार्थियों को यह भरोसा हो कि परीक्षा हाल में बैठते समय उनकी बराबरी किसी पैसे वाले या प्रभावशाली उम्मीदवार से कम नहीं है।

# आधी रात ऋषभ पंत की गुहार या ऋषभ पंत की 'गूगली'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। रात के 12 बजकर 46 मिनट। जब ज्यादातर लोग अपने फोन को एक तरफ रखकर दिन खत्म कर चुके होते हैं, सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक पोस्ट सामने आती है। पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की मांग की जाती है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी। इसे पढ़ने वालों के लिए यह एक अलग तरह की कहानी थी। एक तरफ श्रीलंका का दौरा है। मैदान है। क्रिकेट है। टीम है। वार्मअप मैच हैं। दूसरी तरफ अपने घर लौटने की इच्छा है और उस इच्छा के बीच खड़ी कोई ऐसी परेशानी, जिसके समाधान के लिए राज्य के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी पड़ रही है। अगर पंत सचमुच दिल्ली से दोबारा उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि आखिर वह कौन-सी दिक्कत है, जिसने उत्तराखंड के इस स्टार क्रिकेटर को आधी रात सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से मदद मांगने को मजबूर किया? और यही वह सवाल है, जिस पर क्रिकेट की चमक से बाहर निकलकर बात करने की जरूरत है।

ऋषभ पंत का नाम उत्तराखंड से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ा है कि वह देश के बड़े क्रिकेटरों में शामिल हैं। वह उस पहाड़ से आते हैं, जहां से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाना आसान नहीं होता। पहाड़ में अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है बेटा बाहर जाता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, बड़ा आदमी बनता है और फिर एक दिन गांव लौटना चाहता है। लेकिन लौटने की राह में कई बार वही पुरानी मुश्किलें खड़ी मिलती हैं। सड़क,व्यवस्था,कागज, जमीन व स्थानीय प्रशासन और सबसे बड़ा सवाल क्या पहाड़ में वापस आने वाले व्यक्ति के लिए व्यवस्था उतनी ही सहज है, जितनी बाहर जाने वाले के लिए? पंत की पोस्ट को इसी बड़े सवाल के संदर्भ में देखना चाहिए। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं है।

मान लीजिए किसी आम पहाड़ी परिवार का बेटा वर्षों दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या

**❑आधी रात को मदद की मांग, मैदान से दूर घर लौटने की छटपटाहट**
**❑सवाल सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं, पहाड़ लौटने वालों की राह का**
**❑स्टार क्रिकेटर पंत की आधी रात की पोस्ट ने खड़े किए कई सवाल**

किसी दूसरे शहर में रहने के बाद अपने राज्य में लौटना चाहता है। उसे अगर किसी जमीन, घर, दस्तावेज, प्रशासनिक प्रक्रिया या स्थानीय समस्या के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें तो उसके पास किसे टैग करने का विकल्प है? क्या वह आधी रात मुख्यमंत्री को टैग करके लिख सकता है मुख्यमंत्री जी, मदद करिए? शायद नहीं। ऋषभ पंत कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लाखों लोगों तक पहुंचने वाला सोशल मीडिया है। उनका एक पोस्ट खबर बन जाता है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रशासन भी शायद तुरंत सक्रिय हो जाए। लेकिन यहां असली सवाल यही है जिस काम के लिए एक क्रिकेटर को मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर पुकारना पड़ रहा है, उसी काम के लिए एक सामान्य नागरिक क्या करता होगा?

यह सवाल पंत पर नहीं, व्यवस्था पर है और शायद इसीलिए इस पोस्ट को सिर्फ वायरल पोस्ट मानकर आगे बढ़ जाना ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार लगातार प्रवासियों को वापस पहाड़ लाने, निवेश बढ़ाने और रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने की बात करती रही है। सरकार चाहती है कि पहाड़ से बाहर गया व्यक्ति वापस आए। अपने गांव में बसे। जमीन का इस्तेमाल करे। रोजगार पैदा करे। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन सिर्फ भाषणों से नहीं होता। लोगों को लौटने के लिए भरोसा चाहिए। उन्हें जमीन चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा साफ व्यवस्था चाहिए। उन्हें सड़क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए और ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी काम के लिए किसी बड़े आदमी की पहचान जरूरी न हो।

ऋषभ पंत अगर उत्तराखंड लौटना चाहते हैं तो यह राज्य के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन उनकी घर वापसी अगर किसी प्रशासनिक अड़चन में फंसती है, तो यह भी सोचने का मौका है कि उन हजारों-लाखों लोगों का क्या होता होगा जो उत्तराखंड लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पंत जैसी आवाज नहीं है। पहाड़ का पलायन केवल गांव खाली होने की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की भी कहानी है जो लौटना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पहाड़ छोड़ना आसान है, लौटना मुश्किल। क्यों? क्योंकि बाहर शहर में आपकी पहचान आपकी नौकरी, आपका कारोबार और आपकी मेहनत से बनती है। पहाड़ लौटकर वही व्यक्ति कई बार जमीन, दस्तावेज, स्थानीय व्यवस्था और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच उलझ जाता है और फिर वह सोचता है क्या वापस आना गलती थी?

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

# 'घर लौटने' की राह में खड़ी 'दीवार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। रात के 12 बजकर 46 मिनट। देश के सबसे चर्चित क्रिकेटरों में शामिल ऋषभ पंत श्रीलंका दौरे पर हैं। टीम इंडिया के साथ क्रिकेट के मैदान पर मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट उत्तराखंड की व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की अपील की। यह सिर्फ एक क्रिकेटर की व्यक्तिगत परेशानी की कहानी नहीं है। यह उस उत्तराखंड की कहानी भी है, जो लगातार प्रवासियों से कहता है लौट आइए, अपने पहाड़ आइए, अपने गांव आइए। लेकिन जब कोई लौटना चाहता है तो उसके रास्ते में कौन-कौन सी दीवारें खड़ी हो जाती हैं?और इस सवाल को और गंभीर बना देता है ऋषभ पंत का कद।

ऋषभ पंत कोई सामान्य नाम नहीं हैं। वह उत्तराखंड से निकलकर भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बने। उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, दुनिया के बड़े क्रिकेट मैदानों पर अपनी पहचान बनाई और उत्तराखंड के नाम को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नक्शे पर पहुंचाया। आयकर के लिहाज से भी पंत को उत्तराखंड के प्रमुख करदाताओं में गिना जाता रहा है। ऐसे में अगर राज्य का इतना बड़ा नाम अपने ही राज्य में लौटने से जुड़ी किसी परेशानी के लिए मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से मदद मांग रहा है, तो सवाल सिर्फ पंत का नहीं रह जाता। सवाल व्यवस्था का हो जाता है। सोचिए सरकार कहती है कि उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन होगा। सरकार कहती है कि पहाड़ खाली नहीं होने दिए जाएंगे। सरकार कहती है कि प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश का एक बड़ा क्रिकेट स्टार अपने

**❑ऋषभ पंत की आधी रात की गुहार और उत्तराखंड के दावों का कड़वा सच**
**❑उत्तराखंड राज्य के बड़े आयकरदाता को लगानी पड़ी गुहार तो आमजन कहा**
**❑सवाल जब एक स्टार क्रिकेटर को घर लौटने में दिक्कत तो आम पहाड़ी कहां**

राज्य में दोबारा बसने की कोशिश में किसी अड़चन का सामना कर रहा है और उसे मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर पुकारना पड़ रहा है, तो हमें एक मिनट रुककर पूछना चाहिए कि क्या उत्तराखंड में वापस आना सचमुच इतना आसान है? ऋषभ पंत के पास अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की ताकत है। उनके पोस्ट को कुछ ही मिनटों में हजारों लोग देख सकते हैं। मीडिया उसे खबर बना देता है, सरकार संज्ञान ले सकती है और प्रशासन सक्रिय हो सकता है। लेकिन उस पहाड़ी नौजवान का क्या, जो दिल्ली, मुंबई या देहरादून से अपने गांव लौटना चाहता है? उसके पास कितने फालोअर हैं? वह मुख्यमंत्री को टैग करके कितनी आसानी से अपनी समस्या बता सकता है? शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है।

उत्तराखंड का पलायन सिर्फ रोजगार की कहानी नहीं है। यह व्यवस्था की कहानी भी है। लोग पहाड़ छोड़कर शहरों में गए, किसी ने नौकरी की, किसी ने कारोबार किया, किसी ने बच्चों को पढ़ाया, किसी ने मकान बनाया और अब कई लोग वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन लौटने के साथ जमीन के कागज सामने आते हैं। राजस्व विभाग सामने आता है। स्थानीय अनुमति सामने आती है। सड़क और बिजली की समस्या सामने आती है। स्कूल और अस्पताल का सवाल सामने आता है और सबसे ऊपर आती है सरकारी प्रक्रिया। अगर किसी बड़े क्रिकेटर को भी इन प्रक्रियाओं में मदद की जरूरत पड़ रही है, तो आम आदमी की मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां ऋषभ पंत को लेकर सहानुभूति जताना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी परेशानी को एक केस स्टडी की तरह देखना चाहिए। क्योंकि अगर उत्तराखंड सच में चाहता है कि उसके बाहर गए लोग वापस आएं, तो उसे सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अपना पहाड़ आपको बुला रहा है। पहाड़ बुला रहा है तो रास्ता भी आसान करना होगा।

यह सवाल थोड़ा असहज है, लेकिन

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

# आदि कैलाश के 12 माह यात्रा संचालन की तैयारी शुरू

हमारे संवाददाता

पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में श्रद्धालुओं की आस्था, जनभावनाओं तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिकूल मौसम एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर आदि कैलाश यात्रा वर्षभर संचालित किए जाने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी आशीष भटगंई ने संबंधित विभागों को व्यापक एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप जनभावनाओं और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए आदि कैलाश यात्रा को अधिक सुगम, व्यवस्थित और सर्वसुलभ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ-साथ आदि कैलाश यात्रा का भी प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। आदि कैलाश यात्रा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रभावित नहीं होगी बल्कि दोनों यात्राएं व्यवस्थित रूप से चल सकेंगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सड़क, पेयजल, विद्युत, संचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पार्किंग, स्वच्छता, आवास, भोजन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत खाका तैयार करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सहज एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर वर्षभर यात्रा संचालन से जनपद में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। होटल, होमस्टे, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है।

# उत्तराखंड मुक्त विवि में 'उद्योग-शिक्षा सहयोग' पर मंथन

हल्द्वानी(आरएनएस)। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के उद्योग-अकादमिक प्रकोष्ठ की ओर से उद्योग-शिक्षा सहयोग को बढ़ाने में उद्योगों की भूमिका विषय पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को कौशल से जोड़ने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।कुलपति प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी ने कहा कि उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी समय की मांग है। विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में भी यह शामिल है। इससे न केवल रोजगार क्षमता बढ़ेगी बल्कि उत्तराखंड में कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता को एक नई दिशा मिलेगी। मुख्य वक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज शारदा ने इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, वित्तीय साक्षरता और व्यावहारिक अनुभव पर विशेष जोर दिया।कहा कि यह सहयोग सिर्फ नौकरी तक सीमित न रहकर स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इससे पूर्व निदेशक अकादमिक प्रो.पीडी पंत, प्रो.मंजरी अग्रवाल, डॉ.वीरेन्द्र कुमार, प्रो. आशुतोष भट्ट, डॉ. सुमित प्रसाद, डॉ. कृष्ण कुमार टम्टा, डॉ. कुशा सिंह आदि मौजूद रहे।

## अभियान चलाकर शीघ्र अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

चमोली(आरएनएस)। चमोली जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमण को डीएम ने अभियान चलाकर शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि एनएच पर अवैध पार्किंग पर भी प्रभावी रोक लगाई जाए।बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति व हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुओ मोटो याचिका के तहत एनएच से अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि चमोली जिले में छह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनमें अब तक 359 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 92 को हटा दिया गया है और शेष 267 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है।

# हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा

हरिद्वार(आरएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा-2026' अभियान उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों को व्यापक जनभागीदारी के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान तिरंगा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, साइकिल एवं ई-बाइक रैली सहित विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। साथ ही नागरिकों को अपने घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर तिरंगा फहराने तथा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान के अंतर्गत तिरंगा संगीत कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी, तिरंगा सेल्फी बूथ, शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां तथा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां संभव हो, सरकारी भवनों, पुलों, सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, अस्पताल, विद्यालय, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा थीम पर रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया जाए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर तिरंगा आधारित रंगोली भी बनाई जाएगी। विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में तिरंगे से प्रेरित कला-कृतियां, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित गतिविधियां तथा वंदे मातरम् के अंशों से परिसर सजाने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिल सके।

जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, खंड विकास अधिकारियों और अन्य विभागों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आमजन को भी हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर डिजिटल अभियान में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यक्रम में भारतीय ध्वज संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य विभागों को समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करने को कहा गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

## पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने पर दिया जोर

चमोली(आरएनएस)। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन जनपद चमोली का जिला सम्मेलन नगर पंचायत नंदप्रयाग के सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्तिपत्र भी वितरित किए गए। सम्मेलन में पूर्व विधायक ललित फरस्वाण ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई हैं। यदि गांवों का समग्र विकास करना है तो पंचायतों को अधिक अधिकार, पर्याप्त संसाधन और आर्थिक मजबूती प्रदान करनी होगी। संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा ग्राम स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के संयोजक लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने की। कार्यक्रम में संयोजक हीरा सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार डिमरी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष पृथ्वी रौतेला, प्रवक्ता तेजवीर कंडेरी, मुकेश नेगी, सुखवीर रौतेला, महिला जिलाध्यक्ष ऊषा रावत, जिला पंचायत सदस्य सरोजनी रावत आदि मौजूद रहे।

# सीटी स्कैन व एमआरआई मशीनें हुई पुरानी, नई का भेजा प्रस्ताव

कोटद्वार(आरएनएस)। बेस अस्पताल की सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें अगले साल 10 वर्ष पुरानी हो जाएगी। इससे उनके सुरक्षित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य निदेशालय को नई मशीनों की खरीद का प्रस्ताव भेजा है। बेस अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन 26 मई, 2017 को स्थापित हुई थी। यह मई 2027 में 10 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगी। एमआरआई मशीन 21 जून, 2017 को लगी थी, जो जून 2027 में 10 वर्ष पुरानी हो जाएगी। इन मशीनों ने दुर्घटना में घायल मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि निर्धारित अवधि के बाद इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है। मशीनें बंद होने पर मरीजों को गंभीर परेशानी होगी और जांच सेवाएं रुक जाएंगी। प्रमुख अधीक्षक डॉ. विजय सिंह का कहना है कि सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन अगले वर्ष 10 वर्ष की अवधि पूरी कर लेंगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर नई मशीनों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

## गंगा में सीवर डालने पर पंतद्वीप पार्किंग का शौचालय सीज

हरिद्वार(आरएनएस)। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में शौचालय सीवर का गंदा पानी छोड़े जाने के आरोप के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पंतद्वीप पार्किंग स्थित सार्वजनिक शौचालय से गंदगी सीधे गंगा में डाले जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संज्ञान लिया। डीएम के निर्देश पर उत्तराखंड जल संस्थान (सीवर) के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने टीम से मौके का निरीक्षण कराया। मौके पर टीम की जांच में शौचालय का सीवर गंगा में गिरता मिला। इसके बाद शौचालय संचालक को नोटिस जारी किया गया। साथ ही शौचालय को सीज करते हुए उसका संचालन बंद करा दिया गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि गंगा की स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कहा कि संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

# आईराइज कार्यशाला संपन्न, शिक्षकों ने नवाचारी शिक्षण पद्धतियां अपनाने का लिया संकल्प

अल्मोड़ा(आरएनएस)। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) पुणे तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अल्मोड़ा में आयोजित तीन दिवसीय आईराइज कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला में जनपद के 49 विज्ञान एवं गणित शिक्षकों ने सहभागिता करते हुए गतिविधि आधारित एवं नवाचारी शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह की अध्यक्षता डाइट अल्मोड़ा के प्राचार्य ललित मोहन पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों को विद्यार्थियों के लिए सरल, रोचक और जीवनोपयोगी बनाने के लिए शिक्षकों को गतिविधि आधारित एवं नवाचारी शिक्षण पद्धतियां अपनानी होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं। तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान विज्ञान एवं गणित शिक्षण में नवाचार, गतिविधि आधारित अधिगम, दैनिक जीवन से विषयों का संबंध, गणितीय चिंतन के विकास तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा बढ़ाने जैसे विषयों पर सहभागितापूर्ण सत्र आयोजित किए गए। विषय विशेषज्ञ अंकित जोशी, देवेश कुमार तिवारी, गिरीश चंद्र मठपाल और निम्मी बिष्ट ने विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का संचालन करते हुए विज्ञान एवं गणित की अवधारणाओं को सरल, प्रभावी, रोचक और अनुभवात्मक ढंग से पढ़ाने की अनेक शिक्षण विधियों का अभ्यास कराया। समापन अवसर पर प्रतिभागी शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कार्यशाला ने उन्हें कक्षा-कक्ष में नवाचारी एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की नई दृष्टि प्रदान की है। सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण में सीखी गई शिक्षण पद्धतियों को अपने-अपने विद्यालयों में अपनाने तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों तक उसका लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी 49 प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

# हद से ज्यादा सेब खाने के हैं यह नुकसान, सेहत बनाएगा तो नहीं बिगाड़ जरूर देगा

हर रोज एक सेब खाने से सेहत अच्छा रहता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पोषक तत्व से भरपूर होता है। सेब में पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं इसे खाने से कभी खून की कभी नहीं होती है। आयुर्वेद के मुताबिक सेब खाने से त्वचा संबंधी बीमारी, सीने में जलन, बुखार और कब्ज की परेशानी से राहत मिलती है। सेब में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन-सी और विटामिन-बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप एक दिन 1-2 सेब से ज्यादा खाते हैं तो यह आपकी शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है।

ज्यादा सेब खाने से होने वाले नुकसान

मोटापा- अगर आप जरूरत से ज्यादा सेब खाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे वजन भी बढने लगता है और मोटापा के शिकार हो सकते हैं। इसमें शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है इसलिए यह कैलोरी भी बढ़ा सकती है। फैट भी बढ़ता है।

पाचन : सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर इसे आप ज्यादा खाएंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में गैस बनने लगता है। जिसकी वजह से पेट में दर्द, ऐंठन की समस्या हो सकती है।

ब्लड शुगर: ज्यादा सेब खाने से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। जिससे काफी ज्यादा शरीर को नुकसान हो सकता है। सेब में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से शरीर को काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है।

दांतों: सेब में मौजूद एसिड से दांत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा सेब खाना नुकसानदायक हो सकता है।

# ये फैशन टिप्स जानती हैं आप

आजकल के जमाने में हर लड़की को कुछ फैशन टिप्स मालूम होनी चाहिये जिससे वह बेहतर तरीके से रह सके। अगर आप अपनी नई जींस को ऑल्टर के लिए दे रही हैं तो टेलर को देने से पहले दो बार जींस को वॉश कर लें, क्योंकि धोने के बाद ज्यादातर जींस सिकुड़ जाती है। पुराने कपड़ों से किसी तरह की गंध आ रही है तो इसके लिए आप बोटल में पानी और वोडका को मिलाकर स्प्रे करें। ध्यान रखें बोटल में एक तिहाई वोडका डालें। अगर आपके पसंदीदा हैंडबैग पर तेल के दाग लग जाते हैं, तो इसके लिए आप तेल के स्पॉट के ऊपर बेबी पाउडर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह तक, दाग गायब हो जाएगा। यदि थोड़ा सा दाग अभी भी रहता है, तब इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि दाग पूरी तरह से नहीं चला जाता। डायमंड को हमेशा चमकदार बनाए रखने के लिए उसे लिक्विड डिश वॉश से किसी पुराने ब्रश की मदद से साफकरें। अगर आपके पास कभी स्टोर में जींस ट्राई करने का टाइम नहीं है तो आप अपनी गर्दन से नापकर भी जींस खरीद सकते हैं। इसके लिए आप अपनी गर्दन के चारों ओर जींस की कमर रखें। यदि जींस की कमर आपके गले के पीछे आराम से मिलती है, तो आपकी जींस आपको फिट आएगी। अगर आपके कपड़ो पर लिपस्टिक का दाग लग गया है तो इसे आप बहुत आराम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको लिपस्टिक के स्पॉट पर हेअर स्प्रे लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ना होगा। इसके बाद आप उस कपड़े को वॉश कर लें। अगर आपकी फेवरेट ड्रेस पर वैक्स गिर गई है तो इसके लिए आप उस पर वैक्सिंग स्ट्रीप रखें और ऊपर से गर्म प्रेस करें। वैक्स पिघल जाएगी। इसके बाद आप स्ट्रिप को हाथों पर वैक्सिंग की तरह हटाएंगे तो आपकी ड्रेस से वैक्स आसानी से बाहर आ जाएगी। लेदर शूज से वॉटरमार्क हटाने के लिए, एक कटोरी में ठंडा पानी ले और इसमें सिरके की कुछ बूंद डाले। अब जहां जहां दाग है उन पर मुलायम ब्रश से तब तक स्क्रब करें जब तक दाग हट ना जाएं। अब इसे पूरी रात सूखने दें। अपनी डार्क जींस को धोते समय जब आप उसे आखरी पानी से निकालेंगे तो उस पानी में आधा कप सिरका भी मिला लें। इससे उसकी शेड बरकरार रहेगी। अगर आपक ब्लश या ब्रॉन्जर बैग में टूट गया तो आप इससे लूज पाउडर बना सकती हैं, जो आपकी स्किन से दाग-धब्बों को छुपाने का काम करता है।


## वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन


# 'नई बोतल में पुरानी शराब वाला पैंतरा'

**◆कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बचा पाएगी उत्तराखंड में डूबती नैया**
**◆सोशल मीडिया व बैठकों से निकलकर मैदानी परीक्षा में उतरे नेता**
**◆संतुलन के नाम पर बनाई गई कांग्रेस की इस नई टीम का पूरा सच**
**◆चुनावी रण से पहले संगठन में ऊर्जा या पुराने समीकरणों की वापसी**

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही उत्तराखंड की राजनीति में संगठनात्मक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम के गठन को पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का अहम कदम बताया है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या यह कार्यकारिणी कांग्रेस में नई जान फूंकेगी या फिर केवल पुराने चेहरों और गुटीय संतुलन का दस्तावेज बनकर रह जाएगी। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि नई कार्यकारिणी में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों, जातीय और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है ताकि पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हो सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि संगठन में जगह पाने वाले नेताओं की असली परीक्षा अब मैदान में होगी।

उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक कमजोरी से जूझती रही है। कई जिलों में पार्टी के पदाधिकारी सक्रिय नहीं दिखे, जबकि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी लगातार चर्चा का विषय रहा। भाजपा जहां लगातार बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस अब नई कार्यकारिणी के सहारे संगठन को गति देने की कोशिश कर रही है। नई टीम के सामने सबसे पहला काम निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना होगा। राजनीति में कार्यकारिणी की घोषणा जितनी आसान होती है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही कठिन। कांग्रेस के सामने चुनौती केवल पद बांटने की नहीं बल्कि पदाधिकारियों से परिणाम लेने की है।

प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब हर पदाधिकारी के काम का मूल्यांकन होना चाहिए जो नेता अपने क्षेत्र में संगठन मजबूत नहीं कर पाए, उन्हें केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर बचाने की बजाय जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। भाजपा की लगातार बैठकों, बूथ जीतो अभियान, विकास यात्रा की तैयारी और चुनावी रणनीति के बीच कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को पार्टी का जवाब माना जा रहा है। भाजपा पहले ही चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए केवल नई सूची जारी कर देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और बूथ-बूथ तक अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी।

यदि नई कार्यकारिणी में युवाओं और महिलाओं को पर्याप्त जिम्मेदारी मिली है, तो यह कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। उत्तराखंड के मतदाताओं में बड़ी संख्या युवा वोटरों की है, जबकि महिला मतदाता भी चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इन्हें केवल नाममात्र की जिम्मेदारी देकर छोड़ दिया गया, तो इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में समय-समय पर गुटबाजी की चर्चा होती रही है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अंदरूनी खींचतान संगठन की गति को प्रभावित करेगी। यदि सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं और जिला स्तर तक समन्वय बना रहता है, तो कांग्रेस के लिए यह कार्यकारिणी चुनावी मजबूती का आधार बन सकती है।

राजनीति में किसी भी संगठन की असली पहचान उसके पदाधिकारियों की सूची से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी सक्रियता से होती है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब कांग्रेस के पास बहाने कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्थानीय मुद्दों पर यदि संगठन लगातार जनता के बीच दिखाई देता है, तभी नई टीम का असर चुनाव में नजर आएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। लेकिन चुनावी राजनीति में केवल नई टीम बना देने से जीत नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब संगठन बूथ तक सक्रिय हो, कार्यकर्ता उत्साहित हों और जनता को यह भरोसा हो कि विपक्ष केवल सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि विकल्प भी प्रस्तुत कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई कार्यकारिणी अगले कुछ महीनों में कागज से निकलकर मैदान में कितनी सक्रिय दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव से पहले यही सक्रियता तय करेगी कि कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती की ओर बढ़ रही है या फिर यह बदलाव केवल पदों के पुनर्वितरण तक सीमित रह जाएगा।

## शब्द सामर्थ्य -016

( भागवत साहू )

**बाएं से दाएं**

1. कतार, क्रम, पांत 2. लज्जत, जायका 4. कारण, वजह 7. सुंदर प्रतीत होना, सुखद होना 8. घोड़े आदि का मल 9. अक्सर, ज्यादातर 10. चक्की में पीसना, मसलना, कुचलना 12. धनुष, फौजी टुकड़ी 13. आभूषण, जेवर 15. लहरों का चक्कर, जलावर्त, भ्रमर 17. बायां, विरुद्ध 18. गाना, नगमा 19. लाचार, विवश 22. नमन, प्रणाम 25. चौकी, थाना 26. इकरार, समझौता, ठेका 27. अधिकार होना, सामर्थ्य होना (मुहा.)।

**ऊपर से नीचे**

1. एक प्रदेश जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है 2. हविर्दान के समय उच्चारित एक शब्द, भष्म 3. दन-दन करते हुए 5. बलशाली, बलवाला 6. परिवर्तित करना, पहले से भिन्न हो जाना 7. चांद, चंद्रमा, रजनीश 11. अप्रिय, अरुचिकर 14. मैं का बहुवचन 15. भंगेड़ी, भंग करने वाला, झाड़ू लगाने तथा मैला साफ करने वाला 16. मातृभूमि, स्वदेश 19. मक्खन, माखन 20. बुढ़ापा, धन, ज्वर 21. टालना, हटाना, बहाना करके हटाना 23. सीमा, हद 24. सौ का पाचंवा हिस्सा 25. घोड़े के पैरों में लगाने का लोहे का टुकड़ा, पौधे आदि का डंठल।

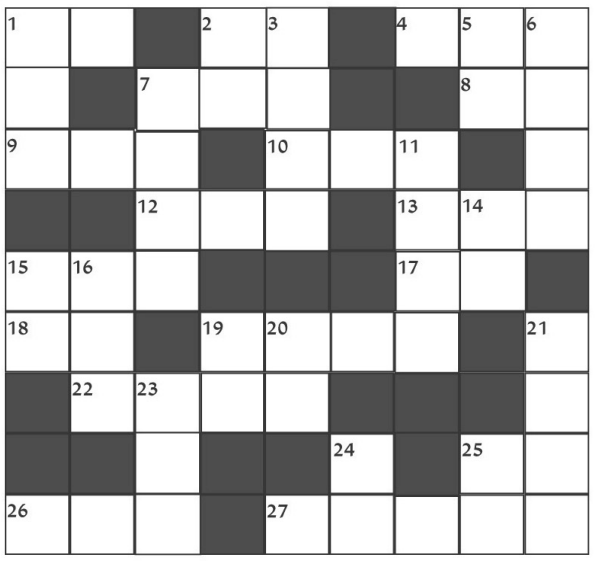

### शब्द सामर्थ्य क्रमांक 15 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वि | ज | य | ■ | ब | नि | या | ■ | दे |
| वा | ■ | ती | त | र | ■ | रा | जी | व |
| ह | मा | म | ■ | स | प | ना | ■ | ता |
| ■ | न | ■ | ■ | ■ | टा | ■ | ■ | ■ |
| दा | व | त | ■ | वि | ना | श | ■ | अ |
| य | ■ | ह | त्या | ■ | ■ | ह | र्जा | ना |
| रा | ह | त | ■ | न | ज | र | ■ | व |
| ■ | वा | ■ | ■ | ■ | मी | ■ | ना | श्य |
| दु | ला | रा | ■ | जा | न | की | ■ | क |

# तमिलनाडु में स्वर्णिम निशाना, रुड़की के एनसीसी कैडेट का हुआ सम्मान

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित इंटर बटालियन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले 84 उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी, रुड़की के कैडेट अक्षय राणा को गुरुवार को बटालियन परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कमान अधिकारी कर्नल जगदीश अलमिया ने उन्हें स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया, जबकि प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमन कुमार सिंह ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

बीएसएम (पीजी) कॉलेज, रुड़की के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र अक्षय राणा ने प्रतियोगिता से पहले 1 जून से 20 जून तक पिथौरागढ़ में विशेष फायरिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद 8 जुलाई से 18 जुलाई तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में एयर पिस्टल शूटिंग का गहन अभ्यास किया। प्रतियोगिता में देशभर के 16 प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले में उन्होंने 371 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और उत्तराखंड के लिए स्वर्ण पदक जीता। अक्षय राणा गौरव सेनानी स्वर्गीय संजीव कुमार के इकलौते पुत्र हैं।

सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने स्वर्ण पदक अपने दिवंगत पिता की स्मृति और अपनी माता श्रीमती अनु को समर्पित करते हुए कहा कि वह भविष्य में भी पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा कर अपने परिवार, एनसीसी और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। कमान अधिकारी कर्नल जगदीश अलमिया ने कहा कि कैडेट अक्षय राणा की सफलता अनुशासन, कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैडेट पूरे उत्तराखंड एनसीसी के लिए प्रेरणा हैं और उन्हें भविष्य की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय बटालियन के प्रशिक्षण अधीक्षक रवि कपूर की विशेष देखरेख में संपन्न हुआ।

उन्होंने कहा कि कैडेट अक्षय राणा की यह उपलब्धि 84 उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी के मुकुट में एक और स्वर्णिम मोरपंख है तथा इससे अन्य कैडेट्स को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर सूबेदार सुनील कुमार, डीईओ संदीप बुड़ाकोटी, हवलदार राजेंद्र सिंह, हवलदार जगत सिंह भंडारी, गौरव सेनानी धर्म सिंह, केयरटेकर प्रियंका प्रजापति सहित बटालियन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

# बीएसएनएल का टावर शोपीस, आक्रोशित उपभोक्ता सड़क में उतरे

पिथौरागढ़ (आरएनएस)। सिर्तोली में एक वर्ष से शोपीस बनें बीएसएनएल टावर को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता जीवन जेठा के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्र हुए।

इस दौरान उन्होंने बीएसएनएल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। वक्ताओं ने कहा कि सिर्तोला में बीएसएनएल टावर पिछले एक वर्ष से शोपीस है। इससे क्षेत्र में रहने वाले लोग नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। कहा कि इससे व्यापार तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही स्कूली बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा कि उन्होंने इस समस्या को जन-जन की सरकार, जनता दरबार में उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किया, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। दानू ने कहा कि अगर शीघ्र ही बीएसएनएल टावर को ठीक कर नेटवर्क सेवा सुचारू नहीं की गई, तो वह ग्रामीणों को साथ लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान दीपक सिंह, विक्रम रावत सिंह, कुंदन सिंह, धीरू रावत, तुलसी देवी, राधा देवी, चन्द्रा देवी, जमुना देवी समेत कई महिलाएं, युवा मौजूद रहे।

# काकरोच पार्टी का नया 'स्टंट'

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। राजनीति बदल रही है। पहले नेता मंच से बोलते थे और जनता सुनती थी। फिर सोशल मीडिया आया, जहाँ नेता भी बोले और जनता ने भी जवाब देना शुरू किया। अब कुछ राजनीतिक दल एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वह कह रहे हैंकृअब क्या बोलती पब्लिक? काकरोच जनता पार्टी ने इसी नाम से अपना नया जनसंवाद अभियान शुरू किया है। नाम जितना अलग है, संदेश भी उतना ही अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि पार्टी जनता की राय सीधे सुनेगी, शिकायतें दर्ज करेगी और उन्हीं के आधार पर अपनी राजनीतिक रणनीति तय करेगी। सवाल यह नहीं है कि अभियान का नाम क्या है। सवाल यह है कि क्या राजनीति सचमुच जनता को सुनना चाहती है, या केवल जनता को यह एहसास दिलाना चाहती है कि उसे सुना जा रहा है?

यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि भरोसे और उम्मीद के बीच भी लड़ा जाता है। अकेले उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आपदा प्रबंधन और पहाड़-मैदान का संतुलन ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव में लौट आते हैं। ऐसे में यदि कोई दल अब क्या बोलती पब्लिक? का अभियान चलाता है, तो जनता भी शायद यही पूछेगी कि क्या हमारी बात केवल रिकार्ड होगी या उस पर कार्रवाई भी होगी? राजनीतिक अभियानों का इतिहास बताता है कि हर

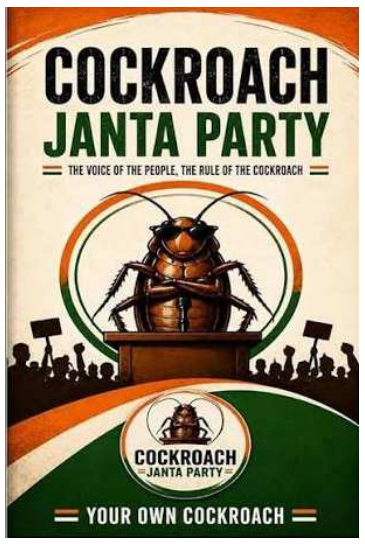


**◆अब सीजीपी देश की जनता के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगी राजनीति**
**◆काकरोच जनता पार्टी का नया दांव या नई राजनीतिक भाषा की तलाश**
**◆जनता से सीधे संवाद का अभियान, सवाल पूछना व जवाब सुनना बराबर**

चुनाव से पहले संवाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा और जन संपर्क अभियान निकलते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही संवाद की गति भी अक्सर धीमी पड़ जाती है। यही वजह है कि जनता अब केवल अभियान नहीं देखती, उसका परिणाम भी देखना चाहती है।

काकरोच जनता पार्टी का यह अभियान यदि केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहता है, तो वह भीड़ तो जुटा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। यदि यह गाँव-गाँव, कस्बों और शहरों तक जाकर लोगों की वास्तविक समस्याएँ सुनता है, उन्हें दस्तावेज बनाता है और समाधान की दिशा में स्पष्ट रोडमैप देता है, तब यह अभियान राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन राजनीति में एक और सच है। जनता केवल बोलना नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसकी बात सुनी भी जाए और उससे भी आगे, उस पर अमल भी हो। आज का मतदाता पहले से अधिक जागरूक है। वह किसी भी दल से एक ही सवाल पूछता है आपकी प्राथमिकता क्या है? केवल सत्ता या समाज? यदि अब क्या बोलती पब्लिक? अभियान जनता की आवाज को चुनावी नारे से आगे ले जाकर नीति निर्माण तक पहुँचाने का प्रयास करता है, तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है। लेकिन यदि यह केवल प्रचार का नया पैकेज बनकर रह गया, तो चुनाव बीतने के साथ इसका असर भी फीका पड़ जाएगा।

राजनीति में सबसे कठिन काम बोलना नहीं, सुनना होता है और उससे भी कठिन काम है सुनी हुई बात को स्वीकार करना। इसलिए इस अभियान की असली परीक्षा पोस्टर, नारे और सोशल मीडिया की पहुँच से नहीं होगी। उसकी परीक्षा तब होगी, जब जनता अपने सवाल रखेगी और पार्टी उनके जवाब देने के साथ-साथ समाधान की दिशा भी दिखाएगी। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज किसी नेता की नहीं होती सबसे बड़ी आवाज जनता की होती है और हर चुनाव में आखिरी शब्द भी वही बोलती है मतपेटी के भीतर।

# गांव की 'धार' पर 'लास्ट पोस्ट'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। पहाड़ में अगर किसी से पूछा जाए कि गाँव कहाँ है, तो अक्सर जवाब मिलता है उस धार के उस पार। यह जवाब केवल दिशा नहीं बताता, बल्कि पहाड़ की पूरी सभ्यता का परिचय देता है। धार... यानी पहाड़ की वह ऊँची रेखा, जहाँ खड़े होकर एक साथ कई गाँव दिखाई देते हैं। जहाँ से सूरज सबसे पहले झाँकता है और शाम की आखिरी किरण भी सबसे देर तक ठहरती है। जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, बल्कि लोकगीत गाती है, जहाँ से बादल नीचे दिखाई देते हैं और इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है। पहाड़ के गाँवों में धार केवल भूगोल नहीं, जीवन का केंद्र रही है। कभी इसी धार पर चरवाहे अपने पशु लेकर निकलते थे। महिलाएँ घास के गट्ठर सिर पर रखकर लौटती थीं। बच्चे स्कूल जाते समय यहीं खेलते थे। बुजुर्ग पत्थरों पर बैठकर मौसम का अनुमान लगाते थे। दूर कहीं धुआँ उठता दिखता तो पता चल जाता किसी घर में चूल्हा जल चुका है। धार, पहाड़ का सबसे बड़ा समाचार कक्ष भी थी। किस गाँव में शादी है, कहाँ देवता की डोली निकलेगी, किस खेत में पहली जुताई हुई, कहाँ बारिश हुई और कहाँ नहीं इन सबकी खबरें मोबाइल नहीं, धार पर मिलती थीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।

आज उसी धार पर घास पहले से अधिक उग आई है, क्योंकि वहाँ चलने वाले पैरों की संख्या कम हो गई है। जिन पगडंडियों पर कभी बच्चों की चहल-पहल होती थी, वहाँ अब झाड़ियाँ हैं। कई गाँवों में घर बंद हैं। ताले लगे हैं। लोग रोजगार की तलाश में मैदानों और महानगरों की ओर चले गए। धार अब भी वहीं है, लेकिन उसे देखने वाली आँखें कम हो गई हैं। पहाड़ का पलायन केवल आबादी का कम होना नहीं है। यह स्मृतियों का भी पलायन है। जब गाँव खाली होते हैं, तो केवल मकान

**❑चरवाहे गए, गीत थमे और पहाड़ के गांव का समाचार कक्ष भी वीरान**
**❑मोबाइल की घंटी और पलायन के सन्नाटे के बीच एक संस्कृति खत्म**
**❑बिना इंटरनेट के जो धार पूरे गाँव को जोड़ती थी आज वहां है सन्नाटा**
**❑पहाड़ों में धार में पीढ़ियों की स्मृतियों, संस्कृति और जीवन दर्शन भी ठप**

नहीं सूने होते, बल्कि धार भी अनाथ हो जाती है। क्योंकि धार को जीवित रखने के लिए पत्थर नहीं, लोग चाहिए। फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज कई युवा वापस गाँव लौट रहे हैं। कोई सेब और कीवी की खेती कर रहा है, कोई होमस्टे चला रहा है, कोई मंडुवा और झंगोरा को फिर से पहचान दिला रहा है। कुछ लोग लोकगीतों और लोकभाषा को डिजिटल दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। यह वापसी छोटी है, लेकिन महत्वपूर्ण है। गाँव की धार आज भी उनका इंतजार कर रही है।

पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि विकास ऐसा हो जो धार की आत्मा को न तोड़े। यदि हर धार पर कंक्रीट ही उग आया, यदि हर पगडंडी सड़क बन गई और हर जंगल केवल सेल्फ़ी का स्थान रह गया, तो पहाड़ अपनी पहचान खो देगा। धार हमें धैर्य भी सिखाती है। वहाँ खड़े होकर समझ आता है कि जीवन केवल भागने का नाम नहीं है। पहाड़ की हवा बताती है कि ऊँचाई का अर्थ अहंकार नहीं, दृष्टि होता है, जो जितना ऊपर होता है, उसे उतना ही दूर तक देखना पड़ता है। शायद यही कारण है कि पहाड़ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी पूँजी बैंक का खाता नहीं, बल्कि गाँव की धार से जुड़ी यादें हैं।

आज जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, तब पहाड़ के गांव की धार हमें यह याद दिलाती है कि विकास का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। क्योंकि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी सबसे ऊँची इमारतों से नहीं, बल्कि उन सबसे ऊँची धारों से होती है, जहाँ खड़े होकर लोग अपने अतीत को याद करते हैं और भविष्य का रास्ता तलाशते हैं। जब अगली बार आप किसी पहाड़ी गाँव जाएँ, तो केवल मंदिर या पर्यटन स्थल ही न देखें। एक बार गाँव की धार पर भी जाकर खड़े होइए। हो सकता है, वहाँ आपको पहाड़ का सबसे सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि उसकी सबसे गहरी आत्मा दिखाई दे जाए। शायद मेरी भी गांव की धार पर यह लास्ट पोस्ट होगी, गांव की तस्वीर भी लास्ट होगी, गांव की संस्कृति, सभ्यता और पुरखों की स्मृतियों के साथ जीवन दर्शन का नजरियां भी लास्ट ही होगा।

# त्यूणी गैस एजेंसी में बायोमैट्रिक ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

विकासनगर(आरएनएस)। जीएमवीएन इंडेन गैस एजेंसी, त्यूणी में बायोमैट्रिक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित किए जाने से ग्रामीण उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश, खराब सड़कें और नेटवर्क की समस्या के बीच उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी प्रबंधन से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। त्यूणी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) इंडेन गैस एजेंसी से क्षेत्र के 60 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण घरों से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और नेटवर्क की समस्या भी बनी हुई है, जिससे समय पर एजेंसी पहुंचना कठिन हो रहा है। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी प्रबंधक से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए बायोमैट्रिक ई-केवाईसी की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं, गैस एजेंसी प्रबंधक आदित्य नौटियाल ने बताया कि एजेंसी के कुल 831 उपभोक्ताओं की बायोमैट्रिक ई-केवाईसी होना शेष है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार उपभोक्ताओं को स्वयं त्यूणी स्थित एजेंसी कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक ई-केवाईसी करानी होगी।

# राइंका रातीघाट में शिक्षक-कर्मियों को नियुक्ति को शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम

नैनीताल(आरएनएस)। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों की पोल अब ग्रामीण ही खोलने लगे हैं। शहीद संजय सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट में वर्षों से शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों से नाराज ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल रणजीत सिंह नेगी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही तत्काल नियुक्तियां न होने पर उग्र आंदोलन को चेताया।ग्रामीणों ने कहा, कि विद्यालय में प्रवक्ता समेत कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सबसे अधिक नुकसान विज्ञान वर्ग के छात्रों को उठाना पड़ रहा है, जबकि कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई भी भगवान भरोसे चल रही है। लगातार बिगड़ रही शैक्षणिक व्यवस्था के कारण विद्यालय में छात्र संख्या भी घटती जा रही है, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी विद्यालयों को मजबूत बनाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। विद्यालय में कनिष्ठ सहायक का पद लंबे समय से रिक्त होने से कार्यालयी कार्य प्रभावित हैं। वहीं, अगले महीने सफाई कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद भी खाली हो जाएगा, जिससे विद्यालय की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए ज्ञापन में मांग की गई, कि सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

## सू- दोकू क्र.016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 6 | | | 1 | |
| 3 | | | 4 | | | 2 | | |
| | | | | | | | 6 | |
| 6 | | | | | 4 | | | |
| | 9 | | 5 | | | 6 | | 1 |
| | | | | | | | | |
| 4 | | 3 | | | 9 | | | 2 |
| | 8 | | 2 | | | | 7 | |
| 1 | | 2 | | 4 | | 9 | | 6 |

**नियम**

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

**सू-दोकू क्र.15 का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |

# स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

हमारे संवाददाता

चमोली। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को भव्य, गरिमामय एवं राष्ट्रभक्ति के माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला सभागार गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है। इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक भवनों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित

**◆गरिमामय एवं राष्ट्रभक्ति के माहौल में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस**
**◆प्रभात फेरी, क्रॉस कंट्री रेस और विशेष स्वच्छता अभियान होंगे आयोजित**

किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रम पूरे उत्साह, अनुशासन एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आयोजित किए जाएं। बैठक में विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को 15 अगस्त की प्रातः प्रभात फेरी आयोजित करने के निर्देश दिए। वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग को जनपदभर में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन विषयक जनजागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम संचालित करने को कहा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने क्रीड़ा विभाग को 14 अगस्त को क्रॉस कंट्री रेस आयोजित करने तथा सभी विभागों को स्वतंत्रता दिवस से पूर्व एवं उसके अवसर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, परियोजना निदेशक आनंद कुमार, उपजिलाधिकारी राज कुमार पांडे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

## सांवणी-सटूड़ी गांव जल्द जुड़ेंगे सड़क से

उत्तरकाशी(आरएनएस)। मोरी विकासखंड के सुदूरवर्ती सांवणी और सटूड़ी गांवों के ग्रामीणों का दशकों पुराना सड़क का सपना अब साकार होने की ओर बढ़ गया है। लोनिवि जखोल-फिताड़ी मोटर मार्ग के बैंचा से सांवणी-सटूड़ी तक पांच किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण 2.90 करोड़ की लागत से कराने जा रहा है। विभाग पिछले दो वर्षों में सड़क का सर्वेक्षण, भूमि हस्तांतरण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। सड़क बनने से सांवणी और सटूड़ी गांवों के 373 परिवार पहली बार मोटर मार्ग से जुड़ेंगे। सांवणी पहुंचने के लिए जखोल से सुपिन नदी पुल तक करीब दो किलोमीटर उतराई और फिर तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है।

वहीं सटूड़ी के लिए पांव गांव से दो किलोमीटर पैदल चलकर सुपिन नदी के लकड़ी पुल तक पहुंचने के बाद चार किलोमीटर कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात और बर्फबारी में यह मार्ग और अधिक जोखिमभरा हो जाता है।

# पुरानी पेंशन बहाली की मांग को सामूहिक उपवास करेंगे कर्मचारी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन (एनएमओपीएस) अल्मोड़ा की ऑनलाइन बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त को चौघानपाटा पार्क में कर्मचारी और शिक्षक एकदिवसीय सामूहिक उपवास रखकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष गणेश सिंह भण्डारी ने कहा कि सामूहिक उपवास के दौरान राजनीतिक दलों से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ओपीएस की बहाली आवश्यक है।

बैठक में 13 सितंबर को देहरादून में प्रस्तावित पेंशन मार्च रैली और मुख्यमंत्री आवास घेराव को सफल बनाने का भी संकल्प लिया गया। इसके लिए जनपद के सभी विकासखंडों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की गारंटी से जुड़ा मुद्दा है। बैठक में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

ऑनलाइन बैठक में जिला संयोजक डॉ. मनोज जोशी, जिला मंत्री भूपाल चिलवाल, प्रांतीय कोर कमेटी सदस्य धीरेंद्र कुमार पाठक, जिला कोषाध्यक्ष दीपक तिवारी, जिला महिला विंग सचिव शांति जुयाल, मंडलीय मंत्री पंकज जोशी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डी.के. जोशी, जिला मीडिया प्रभारी नितेश काण्डपाल सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और सभी विकासखंडों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

# सुसवा नदी का बढ़ता कटाव बना सिमलास ग्रांट के लिए खतरा

विकासनगर(आरएनएस)। लगातार हो रही बारिश के कारण सिमलासग्रांट में सुसवा नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज कटाव झड़ौंद और फारम गांव के समीप नदी का बहाव कृषि भूमि तक पहुंच गया है। जिससे ग्रामीण घबराए हुए हैं।

ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजाजी टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम से संयुक्त निरीक्षण करने की मांग की। सिमलासग्रांट में सुसवा नदी के कटाव के चलते क्षेत्र का ओवरहेड टैंक, खेल मैदान की सुरक्षा दीवार, राजाजी टाइगर रिजर्व की हाथी सुरक्षा दीवार खतरे की जद में आ चुके हैं। इस कटाव से सौर ऊर्जा बाड़ को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं की जानकारी कई बार संबंधित विभागों को दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से सुसवा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग के रेंज अधिकारी से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसका खामियाजा आज किसानों और आसपास के गांवों को भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा कार्य कर दिए गए होते तो आज खेतों और सार्वजनिक संपत्तियों पर संकट नहीं मंडराता।ग्राम प्रधान सुषमा बोरा ने कहा कि सुसवा नदी का कटाव लगातार बढ़ रहा है और गांव की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियां खतरे में हैं। कई बार विभागों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से बिना देरी किए राहत एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की, ताकि ग्रामीणों और किसानों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। इस दौरान ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजाजी टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम से मौके का निरीक्षण कर स्थायी बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात के बीच स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और देर होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है।

# नि:शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। युवा कांग्रेस ने नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।

आज यहां रायपुर विधानसभा के अंतर्गत शिवनगर क्षेत्र में युवा कांग्रेस के राष्ट्र संयोजक भूपेंद्र सिंह नेगी (भुप्पी) द्वारा प्रीतम सिंह के मार्गदर्शन में एक नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श देना तथा आवश्यक दवाइयाँ नि:शुल्क उपलब्ध कराना था। शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राज्य आंदोलनकारी एवं रेड क्रॉस के कोषाध्यक्ष मोहन खत्री ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह नेगी द्वारा किए जा रहे जनसेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं तथा भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। शिविर में अरिहंत हॉस्पिटल की चिकित्सक टीम द्वारा बड़ी संख्या में पहुँचे क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया तथा जरूरतमंदों को नि:शुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं एवं अन्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक शिविर का लाभ उठाया।

इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रीतम सिंह के मार्गदर्शन में जनसेवा के ऐसे कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है और भविष्य में भी रायपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में अजेंद्र गुसाईं, दीपक खंडोरी, दिवाकर ध्यानी, ऋषभ चौधरी, अनुप पाल, सुशील नमोली, दीपक रमौला, इमरान खान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर को सफल बनाने में अरिहंत हॉस्पिटल की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। अंत में भूपेंद्र सिंह नेगी ने सभी चिकित्सकों, सहयोगियों एवं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की सेवा ही उनका सर्वोच्च उद्देश्य है और भविष्य में भी जनहित के ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।

## 'घर लौटने' की राह में खड़ी 'दीवार'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

पूछा जाना चाहिए कि जिस राज्य का नागरिक बाहर रहकर कमाता है, निवेश करता है, टैक्स देता है और फिर अपने घर लौटना चाहता है क्या राज्य की मशीनरी उसके लिए इतनी सरल नहीं हो सकती कि उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक अपनी बात लेकर न जाना पड़े? ऋषभ पंत की लोकप्रियता के कारण यह मामला सामने आ गया। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी परेशानियां कभी सोशल मीडिया तक पहुंचती ही नहीं? कितने पूर्व प्रवासी अपने गांव लौटकर जमीन और प्रशासनिक उलझनों में फंस जाते हैं? कितने लोग वापस आने का विचार इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां काम करवाना मुश्किल है? इन सवालों का जवाब किसी वायरल पोस्ट से नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार को अपनी व्यवस्था देखनी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करने का मामला नहीं होना चाहिए। यह अवसर है। अगर ऋषभ पंत उत्तराखंड में वापस आना चाहते हैं तो सरकार उनकी समस्या का समाधान करे। लेकिन उसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी बनाए जिसमें अगला व्यक्ति मुख्यमंत्री को टैग करने के बजाय एक सरल पोर्टल, एक हेल्पडेस्क या एकल खिड़की के जरिए अपना काम करा सके। क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन पोस्टर से नहीं, सिस्टम से आएगा। उत्तराखंड को ऐसे पहाड़ की जरूरत है जहां किसी ऋषभ पंत को भी अपने घर लौटने के लिए आधी रात को गुहार न लगानी पड़े और अगर पंत जैसे बड़े नाम को आवाज उठानी पड़ रही है, तो उन हजारों सामान्य उत्तराखंडियों के बारे में सोचना जरूरी है जिनकी आवाज मुख्यमंत्री तक कभी पहुंचती ही नहीं। रात के 12 बजकर 46 मिनट पर ऋषभ पंत की पोस्ट वायरल हुई। अब देखना यह है कि सरकार इसे सिर्फ एक क्रिकेटर की समस्या समझती है या उत्तराखंड में घर वापसी की पूरी व्यवस्था पर उठे सवाल के रूप में देखती है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि ऋषभ पंत को मदद मिलेगी या नहीं? असली सवाल यह है जब उत्तराखंड का सबसे बड़ा नाम भी अपने घर लौटने के लिए गुहार लगाए, तो उस आम पहाड़ी की क्या स्थिति होगी जिसके पास न करोड़ों की कमाई है, न सोशल मीडिया की ताकत और न मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच? यही सवाल ऋषभ पंत की आधी रात की पोस्ट को एक क्रिकेट खबर से कहीं बड़ी खबर बना देता है।

# बंद घरों में चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। दो बंद घरों में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से चुराये गये जेवरात बेचकर कमाये गये पांच लाख रूपये, दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त टैंपो बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 4 अगस्त को कोतवाली रानीपुर में टिहरी विस्थापित कालोनी निवासी दो लोगों ने तहरीर देकर बताया गया था कि 29 जुलाई को उनके तथा उनके बगल के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा रात को जेवरात व नगदी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गयी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस टीम द्वारा जब घटनास्थल के आस-पास के सीसी कैमरे खंगाले गये तो उसमें घटना में शामिल एक टैंपो नजर आया। जिससे आरोपी घटना को अन्जाम देकर फरार हो गये, पुलिस टीमो द्वारा उक्त टैम्पो एवं अपराधियो की तलाश हेतु सीआईयू के साथ मिलकर जनपद एवं जनपद से बाहर भी दबिशें देकर वाहन चोरो की तलाश शुरु की। लगातार प्रयासों के पश्चात पुलिस टीम ने घटना में शामिल टैम्पो के हरिद्वार में बीएचईएल की ओर आने की सूचना मिलने पर चैकिंग शुरू की। इस दौरान बीएचईएल स्टेडियम के पास सुरेश्वरी देवी मन्दिर को जाने वाले तिराहे से एक नीले रंग का टैम्पू सहित

एक संदिग्ध आरोपी अक्षय उर्फ गोलू पुत्र होशियार सिंह निवासी टांडा माईदास थाना नगीना जिला बिजनौर उ.प्र. को दबोचकर उनके कब्जे से मृतक स्व.

### ◆पांच लाख रुपये, दस्तावेज व घटना में प्रयुक्त टैंपो बरामद

राजेन्द्र पाल नाम का पुलिस कार्ड बरामद किया गया एवं घटना में प्रयुक्त उक्त टैम्पो को कब्जे में लेकर जब्त किया गया। पकडे गये संदिग्ध आरोपी अक्षय ने पूछताछ पर बताया कि सोनू सैनी व सोनू शर्मा नामक व्यक्ति उसके दोस्त है, जिनके साथ मिलकर उसने दिनांक 29 जुलाई को टिहरी विस्थापित कालोनी में टैम्पू में जाकर दो घरों के ताले तोडकर वहाँ से ज्वैलरी व सामान चोरी किया था, जिसमें राजेन्द्र पाल नामक व्यक्ति का पुलिस कार्ड मैने अपने पास रख लिया था, मै चण्डी चौक से ऋषिकेश तक टैम्पो चलाता हूँ, तो कभी-कभी पुलिस रोकती है, तो मैने यह पुलिस कार्ड अपने पास रख लिया था, मेरे साथी सोनू सैनी व सोनू शर्मा ज्वैलरी बेचने बिजनौर गये थे, और आज हरिद्वार आये है, तथा रावली महदूद निकट डैन्सो चौक के पास स्थित मेरे कमरे में रूके है, और मै अपना हिस्सा लेने जा रहा था। पुलिस टीमो ने पकडे गये आरोपी अक्षय उर्फ गोलू की निशांदेही पर रावली महदूद निकट डेन्सो चौक के पास एटीएम के सामने वाली गली में स्थित मकान से 2 अन्य आरोपियो सोनू सैनी पुत्र सतीश सैनी निवासी टीबडी थाना कोतवाली शहर बिजनौर उ.प्र. व सोनू शर्मा पुत्र रोहताश शर्मा निवासी धामपुर जयत्रा थाना धामपुर जिला बिजनौर उ.प्र. हाल निवासी शिवनगर जयन्तीपुर रोड सीमापुर ब्रहमपुरी थाना कटघर जिला मुरादाबाद उ.प्र. को दबोचकर उनके कब्जे से 5 लाख रूपये नगदी, राजेन्द्र पाल का पैन कार्ड, आधार कार्ड की बरामदगी की गयी। बहरहाल पुलिस ने उन्हे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

# खड़गे की रैली से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन

### ◆नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने दिया एसएसपी ऑफिस में धरना

हमारे संवाददाता

नैनीताल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज होने वाली रैली से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रैली में आने वाली बसों की पुलिस द्वारा जबरन चेकिंग की जा रही है और लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कई विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय में धरना देते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी के इशारे पर पुलिस कांग्रेस की रैली को

प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। नेताओं ने कहा कि रैली में आने वाली

### ◆पुलिस पर रैली में पहुंचने से रोकने का आरोप

बसों को जगह-जगह रोककर चेकिंग की जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी को मुख्यमंत्री का एजेंट बताते हुए भी गंभीर आरोप लगाए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद एसपी क्राइम जगदीश चंद्र मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। उन्होंने पूरे मामले को संभालते हुए आश्वासन दिया कि रैली में आने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। पुलिस के आश्वासन के बाद कांग्रेस नेताओं ने धरना समाप्त किया और खड़गे की रैली के कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए।

## आधी रात ऋषभ पंत की गुहार या ऋषभ पंत की 'गूगली'

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

ऋषभ पंत की पोस्ट को इसी नजरिए से पढ़ना चाहिए। यहां किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि उनकी वास्तविक परेशानी क्या है। क्या मामला संपत्ति से जुड़ा है? दस्तावेज से? प्रशासनिक अनुमति से? किसी अन्य प्रक्रिया से? जब तक पंत या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, तब तक सोशल मीडिया की अटकलों को

तथ्य मान लेना पत्रकारिता नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर पूछी जानी चाहिए। अगर पंत का घर उत्तराखंड है तो उन्हें अपने घर लौटने के लिए मदद क्यों मांगनी पड़ी? और अगर मुख्यमंत्री उनकी मदद करते हैं, तो क्या उसी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जा सकता है कि अगली बार किसी दूसरे प्रवासी को मुख्यमंत्री को टैग न करना पड़े? क्योंकि उत्तराखंड को सिर्फ ऋषभ पंत की वापसी की खबर नहीं चाहिए। उत्तराखंड को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें हर ऋषभ पंत अपने घर लौट सके।

रात के 12 बजकर 46 मिनट पर लिखा गया एक सोशल मीडिया पोस्ट सुबह की खबर बन गया। लेकिन असली खबर शायद वह पोस्ट नहीं है। असली खबर वह सवाल है, जो पोस्ट के पीछे खड़ा है अपने पहाड़ लौटने की इच्छा रखने वाले आदमी के रास्ते में आखिर कौन खड़ा है? और अगर रास्ते में व्यवस्था खड़ी है, तो उसे हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की, सरकार की, प्रशासन की और शायद उन सभी की, जो वर्षों से कहते आए हैंकृ पहाड़ वापस आओ। अब सवाल यह है कि जब कोई वापस आना चाहता है, तो क्या पहाड़ और उसकी व्यवस्था उसके लिए दरवाजा खोलती है? या फिर दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी किसी ऋषभ पंत का होना जरूरी है?

# सीएम ने 9.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9 लाख 87 हजार 17 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को कुल 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9लाख 87 हजार 17 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों को कुल 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। यह भुगतान जुलाई माह 2026 की पेंशन का किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का कमजोर वर्ग, सरकार के परिवार का हिस्सा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि

पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग माता-पिता, विधवा बहन या दिव्यांग भाई को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। हमारा संकल्प प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक, समय पर और बिना किसी परेशानी के उसका अधिकार पहुँचाना है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा माह जुलाई-2026 की पेंशन किश्त का भुगतान किया गया है। इस माह विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों को पेंशन धनराशि का भुगतान किया गया। उक्त लाभार्थियों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सामजिक सहायता कार्यक्रम के 2.15 लाख पेंशनर भी सम्मिलित हैं जिन्हें वर्तमान में स्पर्श नामक नवीन प्रणाली से भुगतान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जुलाई 2026 में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 9,87,017 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया। इसके लिए कुल 146.32 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के कुल 6,15,628 लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से 92.34 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। वहीं विधवा पेंशन के 2,36,983 लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से 35.54 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। दिव्यांग पेंशन के 89,128 लाभार्थियों को 1,500 रुपये की दर से 13.36 करोड़ रुपये, किसान पेंशन के 27,288 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 3.2 करोड़ रुपये तथा परित्यक्ता पेंशन के 8,284 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 99.408 लाख रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा भरण-पोषण अनुदान के 7,383 लाभार्थियों को 700 रुपये की दर से 51.68 लाख रुपये, तीलू रौतेली पेंशन के 2,196 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 26.35 लाख रुपये तथा बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 1.524 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई।

# यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत और 11 घायल

संवाददाता

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के खाई में गिरने की खबर है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 11 अन्य लोग घायल हैं। यह दुर्घटना सुबह सवा 7 बजे के करीब की बताई जा रही है। यह बस बैरागढ़-चंबा मार्ग पर हुआ यह बस शर्मा ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जब यह बस पतवार सर्किल के करीब बैरागढ़ चुलुंग मोड़ पर पहुंची तो अपना संतुलन खो बैठी और 100 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में कम से कम 20-25 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुट गया। उससे पहले ही स्थानीय लोग वह राहत और बचाव के कार्यों में जुट गए। घायलों को तीसा टाउन के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। इस घटना की जानकारी देते हुए चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि इस हादसे की वजह फिलहाल मालूम नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद ही वहां मौजूद स्थानीय लोग तुरंत ही यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे और बाद में पुलिस और एम्बुलेंस टीमें भी मदद के लिए वहां पहुंच गईं। यह बस सुबह करीब 6.30 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी। बताया जा रहा है कि यह अपने शुरुआती केंद्र से करीब 3 किलोमीटर ही आगे आई थी और दुर्घटना का शिकार हो गई।

## टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

पिथौरागढ़। साईबर ठगी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने तेलांगाना निवासी ठग को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा फर्जी मुनाफे का लालच देकर 18.86 लाख का चूना लगाया गया था।जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 21 दिसम्बर को थाना जाजरदेवल में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि उसने टेलीग्राम पर एक ऐसी निवेश योजना देखी, जिसमें कम समय में धनराशि को दोगुना से अधिक करने का दावा किया जा रहा था। अधिक लाभ के लालच में आकर उसने बिना सत्यापन किए विभिन्न किस्तों में कुल 18,96,866 रुपये उक्त स्कीम में निवेश कर दिए। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वह साइबर ठगों के जाल में फंस चुका है, तब तक उसके लाखों रुपये ठगे जा चुके थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान योगेश उत्तम पांचाल, निवासी ग्राम पैदा गुला बड़ा धुला, थाना झुक्कल, तेलंगाना के रूप में हुई। पुलिस टीम ने सर्विलांस एवं तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने सूझबूझ, सतर्कता और प्रभावी रणनीति का परिचय देते हुए उसे हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

# नदी किनारे क्षेत्र पंचायत सदस्य का शव मिला !

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। सुबह सवेरे नदी किनारे क्षेत्र पंचायत सदस्य का शव मिलने से सनसनी फैल गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

मामला कपकोट ब्लॉक मुख्यालय के समीप नगर पंचायत के वार्ड संख्या-7 में खीरगंगा नदी किनारे का है। यहां आज सुबह एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जालेख निवासी 48 वर्षीय तारा सिंह कोरंगा पुत्र सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन सिंह कोरंगा के रूप में हुई है। तारा सिंह वर्तमान में गडेरा क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य थे।

जानकारी के अनुसार तारा सिंह का परिवार जालेख गांव में रहता है, जबकि वह खीरगंगा नदी किनारे स्थित अपने आवास में अकेले रहते थे। सुबह पड़ोस में रहने वाली करीब तीन वर्षीय बच्ची सोनी बरामदे में मुंह धोने के लिए पहुंची। इसी दौरान उसकी नजर तारा सिंह पर पड़ी। बच्ची ने घर जाकर अपनी मां को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आसपास के लोगों को घटना का पता चला।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तारा सिंह की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बताया जा रहा है कि तारा सिंह अपने परिवार में इकलौते बेटे थे। परिवार में उनके माता-पिता, पत्नी और तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है। एक बेटी का विवाह हो चुका है। घटना की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

### जुआ खेलते पांच गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासनगर कोतवाली पुलिस को पता चला कि पृथ्वीपुर के पास बगीचे में कुछ लोग ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच पांच लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ताश के पत्ते नगदी के साथ गिरफ्तार कर लिया।

# स्वच्छ एवं सुंदर शहर के लिए जनसहभागिता जरूरी: डीएम

संवाददाता

देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मण चौक एवं कांवली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

आज यहां जिला विधिक सेवा

### विशेष स्वच्छता अभियान में डीएम एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया प्रतिभाग

प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मण चौक एवं कांवली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान

में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने प्रतिभाग करते हुए स्वयं स्वच्छता अभियान का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम, वेस्ट वॉरियर्स संस्था सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता की। अभियान में 100 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग करते हुए क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान चिन्हित स्थलों पर समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कूड़ा उठान एवं उसके वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि केवल अभियान के दौरान सफाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चिन्हित क्षेत्रों में नियमित निगरानी एवं निरंतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान संचालित किए जाएं तथा स्थानीय नागरिकों को भी इन अभियानों से जोड़ते हुए स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए।

**आर.एन.आई.-** 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

*प्रधान संपादक*
**कांति कुमार**

*संपादक*
**पुष्पा कांति कुमार**

*समाचार संपादक*
**आनंद कांति कुमार**

**कानूनी सलाहकार:**
**वी के अरोड़ा, *एडवोकेट***
**बैजनाथ, *एडवोकेट***

**कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।**
**मो. 9358134808**

*नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।*